ई-न्यूज
24 न्यूज अपडेट
WebSite.: https://24newsupdate.in
उदयपुर, 02 सोमवार दिसम्बर 2024
Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com
वर्ष 1 अंक 269

महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए:निर्मला-रूपाणी 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक करेंगे, शाह के साथ आज पवार-फडणवीस की बैठक



24 न्यूज अपडेट

मुंबई.महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना शिंदे और NCP में एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है।

भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। विजय रूपाणी कल शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मुंबई पहुंचेंगी।

बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। इसमें सीएम का नाम तय होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम का शपथ समारोह होगा।

भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होनी थी। पवार दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन फडणवीस का दौरा अचानक रद्द हो गया है। अब फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में जुड़ेंगे।

विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों से 85 सीटें ज्यादा। भाजपा को 132, शिवसेना शिंदे को 57 और NCP अजित पवार को 41 सीटें मिली हैं।

आज के अपडेट- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान में शपथ समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। विधायकों के साथ शिंदे की बैठक रद्द। डॉक्टर्स ने शिंदे को अभी आराम की सलाह दी है। एकनाथ शिंदे के घर जाकर सांसद संजय शिरसाट ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्रीकांत शिंदे ने शिरसाट से कहा- वह महाराष्ट्र की राजनीति में शामिल नहीं होंगे। शिंदे बोले- जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, "जनता चाहती है कि CM मैं ही रहूं। मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं। मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए।'

रामरहीम को माफी, अकाल तख्त ने सुखबीर को सजा सुनाई:सुखबीर जूठे बर्तन साफ करेंगे, पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल से सम्मान वापस लिया



24 न्यूज अपडेट

अमृतसर. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 9 साल पहले माफी देने और केस वापस लेने के मामले में अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। उन्हें गोल्डन टेंपल में 2 दिन में सेवा करनी होगी। इसी मामले में पंजाब के पूर्व CM स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से 'फक्र ए कौम सम्मान' वापस लिया जाएगा। अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार रघबीर सिंह ने यह सजा सुनाई।

सुखबीर के मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई। इस मामले में 30 जुलाई 2024 को सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने 'तनखैया' (धार्मिक दुराचार का दोषी) घोषित किया था। सुखबीर को 2 दिन सेवा करनी होगी, गले में तख्ती रहेगी

सुखबीर को श्री दरबार साहिब (गोल्डन टेंपल) के घंटाघर के बाहर ड्यूटी करनी होगी। इस दौरान उनके गले में तख्ती और हाथ में बरछा रहेगा। ये सजा उन्हें 2 दिन के लिए दी गई है।इसके बाद 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवादारों वाला चोला पहनकर हाथ में बरछा लेकर ड्यूटी करेंगे। बादल चोट के चलते ये ड्यूटी वह व्हीलचेयर पर बैठ कर देंगे जत्थेदार ने कहा कि सुखबीर इन साहिबों में ड्यूटी के बाद एक-एक घंटा लंगर घर में जाकर संगत के जूठे बर्तन साफ करेंगे। साथ ही एक घंटा बैठकर कीर्तन सुनना होगा और श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना होगा। बाथरूम साफ करने की सजा से सुखबीर बादल को छूट मिली है। क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है। मंत्रियों को भी सजा, लंगर घर में सेवा करेंगे 2015 में बादल कैबिनेट के मंत्रियों को भी कल यानी 3 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक गोल्डन टेंपल के बाथरूम साफ करना होंगे। जिसके बाद नहा कर वह लंगर घर में सेवा करेंगे। बाद में श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना होगा। इन्हें भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तख्ती पहनाई जाएगी।

SC तमिलनाडु मंत्री से बोला-जमानत मिलते ही मंत्री बन गए:कोर्ट देखेगी गवाह दबाव में तो नहीं; सेंथिल बालाजी कैश-फॉर-जॉब स्कैम में आरोपी हैं



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- ये जानकर हैरानी हुई कि सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 सितंबर को जमानत मिलने के दो दिन बाद 28 सितंबर को तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा- हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप (सेंथिल बालाजी) जाकर मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंथिल बालाजी के जमानत को चुनौती दी गई है। याचिका में कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सेंथिल के मंत्री बनने से गवाह दबाव में होंगे।

हालांकि, बेंच ने फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो जांच के दायरे को इस तक सीमित रखेगी कि क्या गवाह दबाव में हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के बाद होगी। 26 सितंबर को जमानत मिली थी, 28 को मंत्री बने साल 2011-16 के दौरान AIADMK शासन में बालाजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। सेंथिल का नाम नौकरी के बदले नकद रिश्वत लेने के घोटाले में सामने आया था। इसके बाद वे दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) में शामिल हुए थे।

मई 2021 में DMK तमिलनाडु की सत्ता में आई। सेंथिल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। 14 जून 2024 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया। 29 जून को उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया गया था।

करीब तीन महीने बाद 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सेंथिल को जमानत दी थी। इसके दो दिन बाद ही 28 सितंबर को सेंथिल की फिर से तमिलनाडु सरकार में मंत्री के तौर पर वापसी हुई थी। वर्तमान में वे ऊर्जा, एक्साइज और उत्पाद मंत्रालय संभाल रहे हैं।

UPSC कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर AAP में शामिल:दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, BJP-कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा टिकट



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. सिर पर गमछा बांधकर UPSC की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया।

ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है, जो पियेगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में ओझा सर AAP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

जमीन बेचकर UPSC की तैयारी की, मेन्स में फेल हुए

अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को UP के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्टमास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनीं। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी। अवध UPSC की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं जहां से आता हूं, वहां या तो आपको IAS ऑफिसर बनना होगा, या फिर अपराधी।'

उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मगर मेन्स में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने BA इन हिस्ट्री, MA इन हिंदी लिटरेचर, LLB, MPhil और PhD इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल कीं।

PM ने 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी:शाह-राजनाथ समेत एक्टर विक्रांत भी मौजूद थे; फिल्म गोधरा कांड पर बनी, तब मोदी गुजरात के CM थे



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. PM नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री-सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे। मोदी पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इससे पहले PM मोदी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की थी। उन्होंने लिखा था- यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है।

UP और MP के CMs ने फिल्म देखी, अपने प्रदेश में टैक्स फ्री भी किया

इससे पहले 21 नवंबर को UP के CM योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के तुरंत बाद उन्होंने UP में इसे टैक्स फ्री कर दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव ने भी 20 नवंबर को द साबरमती रिपोर्ट देखी। उन्होंने फिल्म की स्टारकास्ट की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था।

यूपी के किसान एक हफ्ते तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे:अफसरों से बैठक के बाद समझौता, दोपहर में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी

24 न्यूज अपडेट

नोएडा. यूपी के किसान दिल्ली कूच एक हफ्ते तक नहीं करेंगे। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेस-वे से बैरिकेडिंग हटा दी गई और आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर एक हफ्ते में मांगे नहीं मानी गई, तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े, तो पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया। किसानों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली-यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन, किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि, वज्र वाहन और RAF के जवान तैनात थे, ड्रोन से निगरानी हो रही थी। नोएडा एक्सप्रेस-वे दोनों तरफ से बंद होने और वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था।

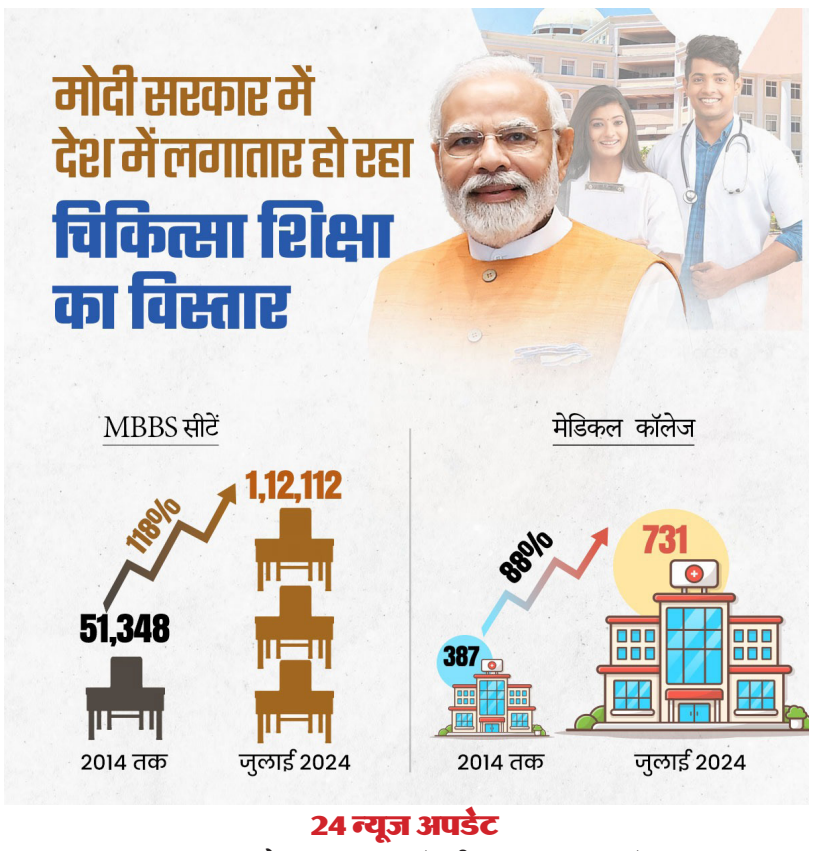
संपादकीय : सुस्त रफ्तार

जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के दावों के बीच चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4 फीसद रहने के आंकड़े स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हैं। हालांकि जुलाई-सितंबर की तिमाही में अक्सर विकास दर सुस्त देखी जाती है, मगर आर्थिक संगठनों और खुद सरकार ने इसके करीब सात फीसद के आसपास रहने का अनुमान लगाया था। अब कहा जा रहा है कि अगली छमाही में विकास दर अच्छी रहेगी। अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही चुक त्योहारी मौसम की होती है, इसलिए इसमें वृद्धि देखी ही जाती है। मगर ताजा आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद को लेकर चिंता पैदा करते हैं। दूसरी तिमाही में सबसे बुरी गत विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की रही। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2.2 फीसद दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.3 फीसद थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की 13.6 फीसद से घट कर 7.7 पर पहुंच गई। इसी तरह आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर घट कर 3.1 फीसद रह गई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12.7 फीसद थी कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि को छोड़ दें, तो ज्यादातर क्षेत्रों में विकास दर सुस्त ही दर्ज हुई है। इस सुस्ती के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि रेपो दर ऊंची रहने और महंगाई पर काबू न पाए जा सकने की वजह से उपभोक्ता व्यय घटा है। इसके अलावा राजस्व घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय भी कम कर दिया गया है। इसका असर सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ा है मगर फिलहाल इन स्थितियों में सुधार की बहुत संभावना नजर नहीं आती। विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर सुस्त रहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रोजगार का संकट बढ़ा है। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार और लोगों की कमाई घटने का स्वाभाविक असर उपभोक्ता व्यय पर पड़ता है। लोग केवल जरूरी चीजों की खरीद करते हैं, विलासिता की और टिकाऊ कही जाने वाली वस्तुओं की खरीद कम होने लगती है। स्वाभाविक ही इससे उत्पादन घट जाता है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि पिछले नौ-दस वर्षों में लोगों की मजदूरी और औसत वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लंबे समय से इस बात पर जोर दिया जा रहा है जब तक लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आर्थिक विकास के सारे उपाय तदर्थ ही साबित होंगे। अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी संतुलन साधने की जरूरत होती है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक तस्वीरें आती रही हैं। चीन आदि देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। इसी तरह, बेशक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के आंकड़े दर्ज हो रहे हों, पर हकीकत में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ रही है। जिस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है, उससे जाहिर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिकुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विकास परियोजनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी हैं कि उसे तदर्थ और अव्यावहारिक उपायों के बजाय बुनियादी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें रोजगार और लोगों की आय में बढ़ोतरी के अवसर पैदा करने होंगे।

हकदार बनाम हकमार

अगर करोड़ों की कीमत वाली बीएमडब्लू कार और घर में वातानुकूलित यंत्रों का इस्तेमाल 'करने वाले भी गरीब और वंचित तबकों के लिए निर्धारित सहायता का लाभ उठाने से नहीं हिचकते, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? यह न केवल प्रशासनिक ढांचे में घुले भ्रष्टाचार का उदाहरण है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि एक समुदाय में समृद्ध या सुविधा - संपन्न माने जाने वाले लोग बहुत कम पैसों के लिए नैतिकता को ताक पर रख सकते हैं, कमजोर तबकों का हक चुराने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। गौरतलब है कि केरल में वित्त आयोग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के संबंध में एक समीक्षा की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि बीएमडब्लू कारों के मालिक और वातानुकूलित मकानों में रहने वाले लोग भी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में राजपत्रित अधिकारियों और कालेज के प्रोफेसरों समेत करीब डेढ़ हजार सरकारी कर्मचारियों के फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल करने की खबरों से लोगों में स्वाभाविक नाराजगी है। निश्चित रूप से यह गलत तरीके से लाभ उठाने वालों के साथ राज्य के प्रशासनिक तंत्र के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का नतीजा है। मगर सवाल है कि यह घोटाला कितने समय से और किसके संरक्षण में चलता रहा ! केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीब तबकों के लिए शुरू की थी। इसके तहत बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को हर महीने सोलह सौ रुपए दिए जाते हैं। मगर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कुछ समृद्ध लोगों ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीबों का हक चुराने में कोई संकोच नहीं किया। दरअसल, केरल के बारे में सामान्य धारणा यही है कि वहां तंत्र के स्तर पर भ्रष्टाचार के उदाहरण कम मिलते हैं और वहां का समाज भी अपेक्षया ईमानदार है। यह एक आम तस्वीर हो सकती है, मगर घोटाले का ताजा मामला यही दर्शाता है कि राज्य के प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त या उसकी अनदेखी करने वाले लोग भी इतना प्रभाव रखते हैं कि करीब डेढ़ हजार लोग अनुचित और अवैध तरीके से वास्तविक जरूरतमंदों की हकमारी कर रहे थे।

चित्तौड़ सांसद के सवाल से चला पता- मोदी सरकार में एमबीबीएस की सीटों में 130 प्रतिशत की वृद्धि



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सवाल लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 697 के रूप में चित्तौडग़ढ़ सांसद सीपी जोशी व अन्य सांसदों ने पूछा। इस सवाल के जवाब में कई अहम तथ्य सामने आए। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या से अब तक 780 तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले 51.348 एमबीबीएस सीटों से अब तक 1,18,137 तक 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। याने मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेजों को खोलने के दिशा में जबर्दस्त काम हुआ है। सवाल का एक भाग झारखंड के चतरा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का है। चित्तौडग़ढ़ सांसद ने विशेष तौर पर चतारा का जिक्र किया है जो झारखंड जिले में स्थित है। इस पर बताया गया कि झारखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सवाल- क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 की तुलना में वर्तमान में देश में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा जिला-वार कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं:

(ख) वर्ष 2014 की तुलना में वर्तमान में देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई हैं।

(ग) क्या मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में वृद्धि से देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या सरकार झारखंड के चतरा जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है।

(ङ) क्या सरकार देश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अपर्याप्त स्टाफ के संबंध में कोई कदम उठा रही है; और



(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(ए) से (एफ)- सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या से अब तक 780 तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले 51.348 एमबीबीएस सीटों से अब तक 1,18,137 तक 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 और 2024-25 में देश में मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत झारखंड के दुमका, हजारीबाग, पलामू, चाईबासा और कोडरमा जिलों में पांच मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा, चतरा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए झारखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन लिफाफे के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी करते समय कॉलेज के भौतिक मूल्यांकन के माध्यम से अपने मानदंडों के अनुसार संकाय और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

धर्मांतरण मुद्दे की राजनीतिक पिच पर सांसद की धुआंधार बल्लेबाजी

संसद में पूछा-राजस्थान में कितने कान्वेंट ईसाई मिशनरी स्कूल?? लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रबंधन कौन करता है?



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। धर्मांतरण व आदिवासियों के मुद्दे पर अपने मुखर व बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले और हाल ही में सलूंबर में भाजपा की चुनावी जीत पर खुशी जताते हुए 'मुगेम्बो खुश हुआ' कह कर सुर्खियों में आए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने लोकसभा मेंएक अतारांकित प्रश्न उठाया है। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने ओर से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से मंत्रजी के माध्यम से कॉन्वेंट स्कूलों का लेखा परीक्षण और वित्तीय प्रबंधन सवाल पूछा गया। लोक सभा में यह अतारांकित प्रश्न संख्या 220 था। इस प्रश्न में कान्वेंट स्कूलों की राज्यवार संख्या, राजस्थान में जिलेवार संख्या और उनके ऑडिट वित्त पोषण आदि के बारे में पूछा गया। जवाब में बताया गया कि राजस्थान में 176 ईसाई मिशनरी स्कूल हैं जिनमें से उदयपुर में 18 स्कूल हैं जो राजस्थान में नंबर के हिसाब से तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर अजमेर है जहां पर 28 स्कूल हैं। दूसरे स्थान पर जयपुर है जहां पर 26 ईसाई मिशनरीज के स्कूल हैं। अब सवाल यह उठता है कि सांसद ने यह सवाल आखिर क्यों व किस प्रयोजन में उपयोगिता के लिए पूछा। जबकि ये सभी आंकड़े अगर वे चाहते तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से मांग लेते, आसानी से उपलब्ध हो जाते। लेकिन संसद के पटल पर इन्हें दर्ज कराने के पीछे मंशा लगता है कि अपने लिए बड़ा राजनीतिक केनवास तैयार करने की है। आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान में धर्मांतरण का मुद्दा बरसों से अहम रहा है। सलूंबर विधानसभा सहित हाल के सभी चुनावों में आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन, लव जिहाद जैसे शब्दों के साहारे सांसद रावत ने मुखर होकर बयान दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि इससे पहले भाजपा के नेता इन मुद्दों पर इतने एग्रेसिव नहीं थे व उनके बयानों में भी ऐसा तीखापन नहीं था जैसा कि रावत के बयानों में है। ऐसा लग रहा है कि रावत आते ही हार्डकोर हिन्दुत्व की छवि के साथ ही आदिवासी हितों की सशक्त पैरवी करने वाले नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं ताकि उनका कद केंद्र की राजनीतिक तक बढ़ सके। शॉर्ट टर्म गेन और लांग टर्म पॉलिटिकल गेन की यह तकनीक भाजपा में आजमायी हुई भी है। कई नेता केवल तीखे बयानों के सहारे ही केंद्र में वह जगह पा गए हैं जो बरसों से जाजमवीर बने नेताओं को नसीब नहीं हुई है।



डॉ. मन्ना लाल रावत ने लोकसभा में पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में संचालित कॉन्वेंट स्कूलों की अवधारणा और राज्य-वार संख्या कितनी है।

(ख) राजस्थान में जिला-वार कॉन्वेंट स्कूलों की अवधारणा और संख्या कितनी है।

(ग) क्या कॉन्वेंट स्कूलों की गतिविधियों की लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

यह आया जवाब - शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी)

(क) से (घ)- शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्तपोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस मंत्रालय में कॉन्वेंट स्कूलों के बारे में विशिष्ट जानकारी/डेटा नहीं रखा जाता है। हालांकि, राजस्थान के लिए राज्यवार और जिलेवार ईसाई अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं। निजी स्कूलों के वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा आदि से संबंधित मामले और संबंधित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय सराडा एवं सेमारी का निरीक्षण



24 न्यूज अपडेट

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी द्वारा कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सराडा एवं सेमारी का निरीक्षण किया और विभागीय कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने निरीक्षण के दौरान ई-फाइल क्रियान्वयन, जन आधार योजना, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, मुख्यमन्त्री ई-ग्राम परियोजना, आय-व्यय लेखे, विभागीय प्रकाशन, संस्था आधार एवं अन्य विभागीय कार्यो पर चर्चा की, साथ ही जन आधार पंजीयन, संशोधन सम्बन्धित समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सॉख्यिकीय डेटा के विश्लेषणात्मक परिणामों को संबंधित विभागो से साझा करने हेतु निर्देशित किया।

निरीक्षण के दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी, विभाग उदयपुर के सहायक निदेशक डॉ पीयूष कुमार भंडारी भी उपस्थित रहे। प्रकाश लाल भट्ट ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सराडा, भारती चतुर्वेदी सांख्यिकी निरीक्षक, भगवान लाल पटेल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सेमारी एवं कविता मीणा सांख्यिकी निरीक्षक ने विभागीय कार्यो की प्रगति से अवगत करवाया।

वंडर सीमेंट लि. में सेफ्टी गेट मीटिंग आयोजित



24 न्यूज अपडेट

वंडर सीमेंट लिमिटेड, आर. के. नगर, निम्बाहेड़ा में आज दिनाकं 02.12.2024 को ''क्रेन एवं लिफ्टिंग सेफ्टी'' की थीम पर मासिक सेफ्टी गेट मीटिंग कम्पनी के यूनिट हेड श्री नितिन जैन की अध्यक्षता में आयोजित कि गई। मीटिंग की शुरुआत सीनियर वर्कमैन द्वारा सेफ्टी फ्लैग फहराकर हुई। इस अवसर पर यूनिट हेड श्री जैन ने सेफ्टी गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए सभी को सुरक्षा के महत्व को जानने और उस पर अमल करने के साथ ही सभी कर्मचारियों को सर्दी के मौसम में कार्य व्यवहार की सुरक्षा के अनुरुप फीट गर्म कपड़ो का उपयोग कर सुरक्षित कार्य करने की सलाह दि तथा वाहन चालको को कोहरे के दौरान वाहन का फोग लेम्प अथवा हेड लाईट ऑन कर सुरक्षित गति से वाहन संचालित करने की सलाह दी। श्री जैन ने इस माह की सुरक्षा थीम ''क्रेन एवं लिफ्टिंग सेफ्टी'' के अनुसार कार्य स्थल पर नियमित सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए कार्य संपादित करने के लिये प्रेरित किया। इस दौरान श्री अमित मेहता, उपाध्यक्ष (ऑपरेशन) तथा श्री राजेन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष (प्रोसेस) भी मंच पर उपस्थित थे। गेट मीटिंग के दौरान महा प्रबन्धक (सुरक्षा) श्री दुर्गादास राठौड़ ने अतिथियों को अभिवादन कर कम्पनी में संचालित सुरक्षा कार्यों से सभी को अवगत कराया। मेकेनिकल विभाग के प्रबन्धक श्री राघवेन्द्र सिंह शक्तावत ने इस माह की सुरक्षा थीम ''क्रेन एवं लिफ्टिंग सेफ्टी'' पर प्रकाश डालते हुए सभी को इससे जुड़े सुरक्षा इंडिकेटर्स की जानकारी दी तथा लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के दौरान सुरक्षा के महत्वों को विस्तार से समझाया। साथ ही इस अवसर पर सुरक्षा से जुड़ी ऑन-द-स्पॉट क्विज़ प्रतियोगिताएं आयोजित कर कर्मचारियों को पुरुस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही कंपनी द्वारा गत माह में सुरक्षा की दृष्टी से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेफ्टी पर्सन ऑफ द मंथ, गुड वर्क डन, बेस्ट नाइट विजिलेंस और बेस्ट सेफ्टी एंगेजमेंट जैसी महीने भर चली प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को भी अतिथियों द्वारा प्रोस्ताहित कर निरन्तर सुरक्षित कार्य संपादन हेतु प्रेरित किया गया। वंडर सीमेंट के सुरक्षा विभाग के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में कम्पनी के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण एवं कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।



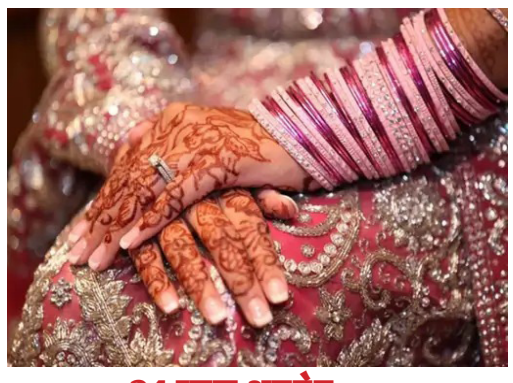
निकाय चुनावों को ज्यादा टाल नहीं पाएगी सरकार, फंस सकता है कानूनी पेंच, कई राज्य सरकारों को लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत चुनावों के मंसूबे के तहत 49 स्थानीय निकायों में प्रशासक लगाने के बाद अब सवाल उठने लग गए हैं कि ऐसा करना वैधानिक भी है या नहीं। आखिर चुनाव कहां तक टाला जाए। कोई हाईकोर्ट चला गया तो सरकार के पास कहने को तर्क ही नहीं है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि चुनाव नहीं करवा रहे हो। तर्क फेल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजीरें दी जाएंगी जिनमें फटकार के साथ चुनाव करवाने के आदेश हैं। हाल ही में पंजाब में चुनाव टालने पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा है कि चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है, हम चुप नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सरपंच संघ ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। इधर, राज्य सरकार जनवरी में होने वाले 6 हजार 857 ग्राम पंचायत के चुनाव भी टालने की तैयारी में हैं व वहां भी प्रशासन लगाए जाएंगे जिनका सरपंच संघ अभी से विरोध कर रहा है। कानूनविद कह चुके हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 5 साल में करवाया जाना अनिवार्य है। आपात स्थिति को छोड़कर चुनाव टालने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान विधान सभा में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी इसका जिक्र कर चुकी है कि निकाय चुनाव सरकार एक साथ ही करवाना चाह रही है। जबकि 73वें संविधान संशोधन में ही यह प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं के 5 साल में चुनाव कराने होंगे, विशेष परिस्थितियों के अलावा चुनाव टालने का प्रावधान नहीं है। संविधान के प्रावधान को राज्य सरकार बदल नहीं सकती, प्रशासक भी 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते, उसके लिए भी पुख्ता कारण चाहिए। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के अनुसार किसी भी पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी होता है। पंचायती राज संस्था को बीच में भंग करने पर भी 6 महीने के भीतर चुनाव जरूरी हैं। जहां कार्यकाल छह महीने से कम है वहां चुनाव कराने जरूरी नहीं हैं। सरकार वार्डों के परिसीमन की आड़ में समय ले सकती है मगर इसमें भी दो से तीन महीने से ज्यादा टालना संभव नहीं हो पाएगा। राज्य में 213 शहरी निकाय हैं। इनके एक साथ चुनाव करवाने हैं। इनमें 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगरपालिकाएं हैं। पंचायतीराज संस्थाओं में 11 हजार 341 ग्राम पंचायतों, 352 पंचायत समितियों और 33 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ करवाना भी चुनौती है। अगले साल 2025 में जनवरी में 6975 ग्राम पंचायतों, मार्च में 704 ग्राम पंचायतों और अक्टूबर में 3847 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन सबके एक साथ चुनाव करवाने के लिए आधी पंचायतों के चुनाव आगे पीछे करने होंगे। दिसंबर 2025 में 21 जिला परिषदों, सितंबर-अक्टूबर 2026 में 8 जिला परिषदों और दिसंबर 2026 में 4 जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

बरात आने से पहले दूल्हे के पास पहुंच गया दुल्हन का अश्लील वीडियो



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. चूरू। बारात आती उससे पहले ही दुल्हन का अश्लील वीडियो दूल्हे व उसके परिवार के पास पहुंच गया। जब वधू पक्ष ने फोन पर पूछा कि बारात क्यों नहीं आई तो कहा कि अब नहीं आएगी। कारण पूछा तो होंश उड़ गए। अब युवती के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर सूरत (गुजरात) भेजी है। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती के दादा ने बताया कि उनका बेटा-बहू और उसके बच्चे गुजरात के सूरत में कपड़े का व्यापार करते हैं। पिछले दिनों उसकी 23 साल की पोती की सगाई सीकर जिले में की गई थी। उसके निकाह की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। उन्होंने बताया- 10 नवंबर को घर पर बारात का इंतजार हो रहा था। बारात आते ही निकाह किया जाना था, लेकिन बारात नहीं आई। इस पर उन्होंने दूल्हे के पिता को फोन कर इस बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि बारात नहीं आएगी। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आपकी पोती का एक अश्लील वीडियो उनको भेजा गया है। दूल्हा पक्ष ने आरोप लगाया कि दुल्हन के किसी और के साथ संबंध हैं। पीड़ित के परिजनों कहना है कि दूल्हे के पिता के आरोप के बाद उन्होंने पोती से पूछताछ की। उसने आपबीती बताई। कहा कि सूरत में जब कॉलेज में पढ़ती थी। तब जीशान (25) निवासी सूरत (गुजरात) पीछा करता था। जबरदस्ती उसके साथ जान-पहचान बनाई और उसके फोटो ले लिए।युवक ने उसकी फोटो को गलत तरीके से मोडिफाई किया और उनको सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर रेप किया। रेप के समय भी फोटो ली और धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। शादी करने का दबाव बनाता था। अब अश्लील वीडियो ससुराल वालों को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया।

सलूंबर जिले की जावर माइंस थाना पुलिस ने 24 घंटे पहले हुई घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

जावर माइंस थाना अधिकारी पवन सिंह ने बताया कि रविवार शाम को उदयपुर सलूंबर स्टेट हाईवे पर अंधेरे में पत्थरबाजी कर कहीं वाहनों के कांच तोड़ दिए । घटना औडा स्कूल के सामने हुई। बदमाशों ने शराब के पैसे के लिए हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों को रुकवा कर शराब के पैसे मांगे । जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर केवड़ा चौकी से पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा । जहां पर लंबा गाड़ियों का जाम लगा हुआ था ।और अंधेरा का फायदा उठाते हुए कुछ बदमाश वाहनों पर पत्थर बाजी कर रहे थे। पुलिस ने उनको मना किया तो वह ज्यादा पथरबाजी करने लगे । और वह मौके से फरार हो गए । जिस पर पुलिस ने एक टीम घटित कर रात भर बदमाशों की तलाश की इस दौरान मुखबिर से पता चला कि तीन चार लड़के हैं जो कुछ दिनों से बांसवाड़ा सलूंबर हाईवे पर आए दिन राहगिरो से शराब पीने के लिए पैसे मांगते हुए पथरबाजी कर रहे हैं । पुलिस ने संदिग्ध भेरूलाल, कैलाश,गणपत, भूपेंद्र को डिटेल कर पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात करना कबूल किया । जिस पर पुलिस ने भेरूलाल पिता लक्ष्मण लाल मीणा निवासी ओड़ा, कैलाश पिता खुमा मीणा निवासी ओड़ा, भूपेंद्र पिता कैलाश मीणा निवासी ओड़ा, गणपत लाल पिता बाबूलाल मीणा निवासी रेला को गिरफ्तार किया । पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि या बदमाश काफी समय से घर पर बेरोजगार घूम रहे थे मोबाइल व मौज शोक के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए अपने मौज पूरा करने के लिए इधर-उधर सुनसान मकान व दुकानों की रेखी करते व रात के समय में मौका देखकर उदयपुर सलूंबर स्टेट हाईवे पर रुपए को लेकर पत्थर बाजी करते ।

आवासन मंडल ने विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण:प्रस्तावित 100 फीट रोड के बीच कई योजनाएं अटकी थीं, पुलिस जाब्ता रहा मौजूद



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर. आवासन मंडल उदयपुर ने सोमवार को सेक्टर-9 वीआईपी कॉलोनी के पीछे प्रस्तावित 100 फीट बनाने में आड़े आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण होने से यहां कई सालों से आवासीय योजनाएं अटकी थीं। जिन्हें अब विकसित करना आसान होगा। अतिक्रमण के दौरान स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए और विभागीय अफसरों से उनकी बहस हो गई। विभाग का कहना था कि प्रस्तावित रोड के बीच आने वाले सभी खातेदारों को नियमानुसार पट्टे दे दिए हैं।

आवासन मंडल की टीमें सवीना थाना पुलिस के सहयोग से 3 से 4 जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और विरोध के बीच अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कराई। जेसीबी द्वारा वहां बने बाड़े, दीवार आदि ध्वस्त कर दिए। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार रणजीत सिंह, उप आवासन आयुक्त कालूराम मडावरिया और एक्सईएन अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। पहले 2 बार अतिक्रमण हटाने पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हुए जानकारी अनुसार वर्ष 2000 में यहां 100 फीट रोड प्रस्तावित हुआ था। लेकिन एक खातेदार का इस पर अतिक्रमण होने से विभाग की योजनाएं अटकी पड़ी थी। इसे लेकर लगातार कई बार समझाइश का दौर चल रहा था। नोटिस भी दिए जा चुके थे। यहां तक विभाग इससे पहले 2 बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए मौके पर गया था लेकिन खातेदार द्वारा इसके लिए मोहलत मांग ली गई। फिर भी मामला टलता गया।

वर्ष 2013 में 600 फ्लैट आवंटित हुए, अतिक्रमण होने से नहीं बन पाए इस क्षेत्र में आवासन मंडल की ओर से वर्ष 2013 में 600 फ्लैट्स की लॉटरी खोली गई थी लेकिन अतिक्रमण होने से फ्लैट्स आज तक नहीं बन पाए। इसके अलावा विभाग की यहां आगामी आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं लेकिन प्रस्तावित 100 फीड रोड का रास्ता साफ होने पर इन योजनाओं को मूर्त रूप देने की राह आसान हो गई है।

आवासन मण्डल की पानेरियों की मादड़ी में कार्रवाई का विरोध, बिना मुआवजा दिये किसानों की भूमि में अतिक्रमण का आरोप



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। पानेरियों की मादड़ी के खातेदारों ने आज अतिक्रमण कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि पर आवासन मण्डल द्वारा बिना मुआवजा दिये जबरन किसानों की जमीन के अन्दर पुलिस बल के साथ किसानों एवं महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की व जोर-जबरजस्ती करके अतिक्रमण कर किसानों को बेदखल करने का प्रयास किया गया है। किसानों के भारी आक्रोश एवं विरोध से जिला कलेक्टर ने आवासन मण्डल को पत्र लिखा जिसमें काश्तकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रत्र क्रमांक प. 6 (29) नगरीय विकास विधि/3/2020 के पैरा संख्या-3 खण्ड (8) के पश्चात् नवीन खण्ड (8-ए) दि. 4 नवंबर 2020 के तहत 15 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत देने के आदेश दिये। इस पर आवसन मण्डल ने सन् 2020 में कई खातेदारों 20 प्रतिशत आवसीय एवं 5 प्रतिशत कॉमर्शियल मुआवजा दिया गया है। इस पर कलेक्टर आवासन मण्डल के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर किसानों को आश्वस्त किया कि यदि इसी जमीन से लगी जमीन का मुआवजा आवसन मण्डल द्वारा 25 प्रतिशत दिया है तो निश्चित में रूप से आपको 25 प्रतिशत का आंवटन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या किसान मौजूद रहे। लेकिन पुलिस बल एवं आवासन मण्डल के अधिकारियों ने किसानों की बिलकुल नहीं सुनी।

राजनीतिक रोटियां सिक गईं, भूतपूर्व भी हो गए, अब तो जेबें ढीली करों पार्षदों!!!



24 न्यूज अपडेट

तीन महीने पहले जोश-खरोश से किया था देवराज के नाम एक महीने के वेतन देने का वादा, अब तक किसी ने एक रूपया तक नहीं दिया, आर्थिक मदद की गति भी धीमी- 50 लाख मिलने थे, 30 ही मिले देवराज हत्याकांड के बाद पार्षदों ने बड़े ही जोश के साथ एक महीने का वेतन देने का वादा किया था जो तीन महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक में लिया गया यह संकल्प अब तक पूरा नहीं होना कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या उस समय का जोश केवल दिखावे के लिए था। बाहर से आ रहे बड़े नेताओं के सामने नंबर बढ़ाने के लिए था। या फिर केवल राजनीति चमकाने की मंशा थी। या फिर केवल फोटो इवेंट से सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाओं को कैश करने की मंशा थी। क्योंकि यदि मंशा सही होती व संवेदनाएं गहरी होतीं तो इधर घोषणा हुई, उधर आर्थिक मदद हाथों हाथ देवराज के घर पहुंच जानी थी लेकिन किसी को भी अब तक इस बारे में ध्यान में ही नहीं आया है। एक महीने के वेतन के लिए भी जेब ढीली नहीं कर पा रहे हैं। अब पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है व सभी भूतपूर्व हो चुके हैं। ऐसे में मदद कौन देगा यह बडा सवाल उठ रहा है। पार्षदों ने फेयरवेल पार्टी भी कर ली है और कार्यकाल के अंतिम दिनों में कुर्सी की जंग भी लड़ ली गई है मगर इस बात के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं लगती है। परिजनों ने कहा कि निगम की ओर से मिलने वाली सहायता का इंतजार कर रहे है। देवराज के पिता पप्पू मोची ने कहा कि निगम के पार्षदों की ओर से अभी तक एक रूपया नहीं मिला है। इसके अलावा 50 लाख की मदद की बात थी, अब तक केवल 25 लाख मिले हैं। बाकी का बचा पैसा कहां, कैसे कब व कौन देगा उनको नहीं पता। समझौता वार्ता में यह भी तय हुआ था कि देवराज के परिजनों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी लेकिन देवराज के पिता ने संविदा की अस्थायी व कम वेतन वाली नौकरी नहीं ली। अब सहेलियों की बाड़ी में केबिन लगाने पर सहमति हुई है।

आमजन में भय : बस स्टैंड पर कटी कॉन्स्टेबल की जेब



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. चित्तौड़गढ। आजकल चोरों के हौसल सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। पहले केवल आम आदमी शिकार होता था मगर आजकल तो यह पुलिस वालों पर हाथ डालने से भी नहीं हिचक रहे हैं। डर खत्म सा हो गया है। बीती रात भीलवाड़ा एसपी ऑफिस में तैनात एक कांस्टेबल की ही जेब कट गई। कांस्टेबल अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ के पांडोली स्थित झांतला माता मंदिर में दर्शन करने आए थे। बताया गया कि वापस भीलवाड़ा आते समय जब कांस्टेबल साहब रोडवेज बस में बैठे। इसी दौरान किसी ने पर्स मार लियां इसके बाद रोडवेज बस स्टैंड के सामने कोतवाली थाने में जानकारी दी गई। पुलिस आई व सभी सवारियों और उनके सामानों की तलाशी ली लेकिन पर्स का पता नहीं चला। बताया गया कि भीलवाड़ा एसपी ऑफिस में तैनात कॉन्स्टेबल प्रहलाद अपने परिवार के साथ रविवार को पांडोली स्थित झांतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। बस में अचानक पता चला कि पेंट की पिछली जेब में रखा पर्स गायब है। ड्राइवर ने तुरंत रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित कोतवाली थाने को बताया। पुलिस आई मगर तब तक चोर अपना काम करके जा चुका था। पर्स में लगभग ढाई हजार रुपए और अन्य काड्र्स, डॉक्यूमेंट्स भी थे।

प्रशासक के राज में कचराधारी वाहन चला बाजार में, कुछ यहां गिरा, कुछ वहां गिरा



24 न्यूज अपडेट

सड़क पर सरपट दौड़े जा रहा ये कचराधारी डंपर वाहन नगर निगम के प्रशासक को ओपन चैलेंज दे रहा है कि कितने भी नियम बना लो, चलनी तो ठेकेदार की है। खुले में रपटता हुआ यह कचरा अशोक नगर से होते हुए शक्तिनगर के व्यस्त बाजार से गुजरा। इस दौरान कुछ कचरा यहां गिरा तो कुछ वहां गिरा। पीछे चलने वाले भी हैरान हो गए कि ठेकेदार अधिकारियों को रिश्वत खिलाते-खिलाते कितने बेखौफ हो गए हैं। उनको कार्रवाई और नियमों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ऐसी कचरा गाड़ियां इन दिनों दिखना आम हो गई है। बेपहरवाही का यह आलम कहीं इसलिए तो नहीं कि अब निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है। पार्षद इस तरफ आंख उठा कर भी नहीं देख रहे हैं। जबकि नियमानुसार कचरे को ढंक कर ही परिवहन किया जाना जरूरी है। खुले में कचरा जाएगा तो बीमारियों की सौगात भी गली-गली बांटता फिरेगा। मजे की बात यह कि यह कचरा ले जाने वाला वाहन निगम के ऑफिस के पास से भी गुजरा लेकिन मजाल कि किसी की नजर पड़ जाए। अब शहरवासियों को ऐसा लग रहा है कि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते, तब तक इसी प्रकार अफसरों की मेहरबानी से ऐसे ओपन कचरा वाहन सड़कों पर भागते हुए नजर आएंगे।

मेनारिया समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, मेनारिया समाज पानेरियों की मादड़ी के तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह रॉयल खेड़ा स्टेडियम, कानपुर में किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि मेनारिया समाज ग्राम सभा, पानेरियों की मादड़ी के उपाध्यक्ष तुलसीराम कचरावत, बंशीलाल नाथावत, महामंत्री किशन नेतावत, विशिष्ठ अतिथि धनलाल मेनारिया, लक्ष्मण मानावत प्रवक्ता कैलाश मेनारिया, गिर्वा जोन के उपाध्यक्ष अर्जुन मेनारिया, मंत्री भूपेश मेनारिया, औंकार मेनारिया, उदयलाल मेनारिया, दिपलाल मेनारिया थे। मेनारिया समाज खेल मंत्री राजेश मेनारिया ने बताया कि प्रथम सेमीफाईनल श्रीराम मोटर्स बनाम श्रीजी डवलपर्स, द्वितीय सेमीफाईनल रिद्धी सिद्धी एडवरटाइजर्स बनाम एपेक्स सोलर जिसमें रिद्धी सिद्धी एडवरटाइजर्स विजयी रही। फाइनल मैच रिद्धी सिद्धी एडवरटाइजर्स बनाम श्री राम मोटर्स के मध्य रहा जिसमें पहले बल्लेबाजी श्रीराम मोटर्स ने 10 ओवर में 99 का लक्ष्य दिया जिसमें रिद्धी सिद्धी एडवरटाइजर्स ने 88 रन 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में बना सकी एवं श्री राम मोटर्स 10 रन से विजयी रही। बेस्ट बॉलर कुणाल पुरोहित, बेस्ट फिल्डर जैम मानावत, बेस्ट बैट्समैन अश्विन मेनारिया एवं मैन ऑफ द सीरिज कुणाल पुरोहित रहे।

इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा उप विजेता एवं विजेता टीम को ट्रॉपी प्रदान की गयी। समापन समारोह के दौरान दिशान्त मेनारिया, तरूण मेनारिया, यशवन्त मेनारिया, सौरभ मेनारिया एवं अन्य कई मेनारिया समाज के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

चित्तौड़ में सेंटपॉल स्कूल स्टॉफ क्वार्टर में मिला झाड़ोल की युवती की लाश, गले में बंधी थी रस्सी



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. चित्तौड़गढ़। यहां पर सेंट पॉल स्कूल के परिसर में स्टॉफ क्वार्टर की सीढ़ियों पर युवती की लाश संदिग्ध हालत में मिली जिसके गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थ। शव सीढ़ियों पर पड़ा था। पुलिस और स्कूल स्टॉफ ने कहा कि सुसाइड कर लिया है। परिजन उदयपुर के रहने वाले हैं। परिजनों के आने के बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया जाएगा। सूचना पर मौके पर सीआई गजेंद्र सिंह मय जाब्ता पहुंचे और मौका देखा। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने स्टॉफ क्वार्टर में युवती झाड़ोल, उदयपुर निवासी रीना (22) पुत्री मोतीलाल पारगी का शव सीढ़ियों पर मिला। रीना स्टॉफ क्वार्टर में कमरे में रहती थी और स्टॉफ के लिए खाना बनाने का काम करती थी। लगभग दो साल से यहीं रहकर काम कर रही थी। मैनेजर बाबू सीरिया ने बताया कि सुबह 11 बजे सिस्टर सुगन्या से जानकारी मिली कि खाना बनाने वाली रीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सदर थानाधिकारी गजेंद्र सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। सिस्टर सुगन्या ने बताया कि रीना ने सुबह 8 बजे सबके लिए नाश्ता बनाया था। सुबह 10.30 बजे चाय बनाने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। अमूमन हर रोज वो पहली ही घंटी में फोन उठा लेती है। आज फोन नहीं उठाया तो अनहोनी की आशंका हुई और मौके पर गए तो देखा कि सभी दरवाजे, खिड़कियां बंद थी। रसोई के पास हॉल था, जहां से एंट्री करके रसोई तक पहुंचे। दरवाजे के कोने से दूसरी मंजिल की तरफ देखा तो रीना का हाथ और पांव लटका दिखा। रसोई का दरवाजा तोड़ा गया। फिर दूसरी मंजिल में जाकर देखा तो रीना की लाश पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है रीना की बड़ी बहन पहले काम करती थी। शादी के बाद उसके कहने पर रीना को नौकरी दी गई थी। प्रतापनगर में उसकी एक रिश्तेदार गीता रहती है, जिसने रीना के परिजनों का नंबर दिया था।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।